क्रम सं०	परियोजना का नाम		क्षमता (मे०व०)
	तमिलनाडु		
9.	नारिभानाग गैस टर्बाइन	जी टी–1	5
		जी टी–2	5
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :		
	मणिपुर		
10.	डी जी सैट्स इम्फाल	युनिट–1	
		युनिट–2	
	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
11.	चेतम डी जी सैट्स		5 × 1.5
	त्रिपुरा		
12.	रोखिया गैस टर्बाइन	जी टी–1	8
		जी टी–2	8
13.	बारामुरा जी टी (एन ई सी)	जी टी–3	6.5
		जी टी–गैस टर्बाइन	
		एस टी–स्टीम टर्बाइन	

Satellite Telecom Network by A. U. S. Company

*108. SHRI E. BALANANDAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Hughes Escorts Communications Limited, a U.S. multi-national Company has offered to set up and operate satellite based telecom network in India;

(b) if so, what are the details thereof including the places proposed to be covered and the services proposed to be provided under the said network; and

(c) what are the terms and conditions proposed by the above multi-national company ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) Sir, M/s. Hughes Escorts Communications Ltd., an Indian registered joint venture Company has submitted a proposal for setting up a closed user group high speed data network.

(b) Details are given in the statement (*See* below).

(c) The company in its proposal has stated that it will abide by all the terms and conditions laid down by the Department of Telecommunications.

Statement

Details of the Proposal

The proposal submitted by M/s. HECL is for providing 64 Kbps data domestic service via the satellite.

The service would be available to all sites scattered throughout India like remote hilly towns, rural areas, wayside industrial establishments, large island communities, corporate sectors etc. The joint venture is set up for production of VSAT in the country so that all equipment is indigenously available against Rupee Payment.

Salient points of the proposal are as follows :

— VSAT service would use Very Small Aperture Terminal at the user's premises.

— Space segment would be provided by DOT through one of the INSAT satellites on rental basis.

— VSAT equipment at the User's premises would be maintained by HECL complying with the MTTR norms of DOT. The service would be a domestic country wide service. Quality of the service would be as per the standard norms of the DOT.

— Installation of the equipment would be tested and approved by DOT before being commissioned.

ऋण-राहत योजना के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि का भुगतान

@*109. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ऋण राहत योजना के अधीन अवशेष दावों की राशि की अदायगी की मांग करते हुए कृषि मंत्रालय को कई पत्र लिखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और अवशेष दावों की राशि की प्रतिपूर्ति करने में क्या-क्या बाधाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिनांक 16 नवम्बर, 1992 को उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य की मुद्रा स्थिति नीचे दी गई है :—

	ऋणकर्ताओं की संख्या जिन्हें राहत दी गई	राहत की राशि (करोड़ रुपए)
(क) सरकारी क्षेत्र के बैंक	9,69,444	287.87
(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5,24,861	112.47
(ग) सहकारी समितियां :		
(i) राज्य सहकारी बैंक	33,84,250	545.95
(ii) राज्य भूमि विकास बैंक	3,03,098	101.33
कुल :	51,81,653	1047.62

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उस तारीख तक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंकों को ऋणों और अनुदानों के रूप में 477.43 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई और उसका भुगतान किया गया । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सभी राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

@पूर्वस: तारांकित प्रश्न 69, 27 नवम्बर, 1992 से स्थानान्तरित ।